भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1450
बुधवार, 12 मार्च, 2025 (21 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

पीएसीएस के डिजिटलीकरण की स्थिति

1450 # श्री संजय सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में अब तक कितनी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है और पीएसीएस के डिजिटलीकरण और उन्हें कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) से जोड़ने हेतु निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना (सीएसपीसीपी) हेतु आवंटित बजट और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है तथा अब तक उक्त परियोजना का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 63,000 पीएसीएस के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा है, यदि हां, तो अब तक इस परियोजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग) भारत सरकार द्वारा ₹2,516 करोड़ (जिसमें भारत सरकार का हिस्सा ₹1,528 करोड़ है)) की कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है । इस कॉमन ERP सॉफ्टवेयर को देश भर में परियोजना के सभी पैक्स को उनके सभी कार्यों, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट, के डाटा का संकलन करने के लिए दिया जा रहा है । यह सॉफ्टवेयर राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलनशील है ।

ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एक कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन (MIS) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में कुशलता लाएगा । इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में सुधार आएगा जिससे ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन

लागतों में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होगा ।

अब तक, 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से 67,930 PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार का हिस्सा के रूप में 741.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 27 जनवरी 2025 तक, 60,382 PACS को हार्डवेयर वितरित किया गया है, जो कुल लक्ष्य का 89% है। कुल 50,455 PACS (74%) को ERP प्रणाली में शामिल किया गया है, जबकि 40,050 PACS (59%) लाइव हो चुके हैं। परियोजना की समाप्ति तिथि 31.03.2027 है।

***